साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 22 फरवरी 2021, वर्ष-6, अंक-47

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

कमल सुविधा केंद्र पर किसान दर्ज कराएंगे शिकायत

प्रदेश की मंडियों में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में सभी मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाए जाएंगे। मंडियों को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। किसानों को असली खाद और दवाइयां, उच्च गणवत्ता वाले बीज, बाजार की तुलना में कम दाम पर मंडियों में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था मप्र सरकार कराएगी। यह बाम मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को फसल बीमा का लाभ और मुआवजे की व्यवस्था की गई है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खराब हुई फसलों का भी बीमा करवाया गया। इसी प्रकार वन ग्रामों को राज्स्व ग्राम से लिंक करके आदिवासी जनसंख्या को भी फसल बीमा के लाभ के लिए पात्र बनाया गया है। मध्यप्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां कम आबादी वाले ग्रामों को पटवारी हल्का में शामिल होने के कारण किसी भी प्रकार फसल आपदा में बीमे का विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने ग्रामीण विकास के द्वार खोले हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र तथा भूमि स्वामित्व प्राप्त होगा जिससे वह बैंक से कर्ज लेकर अपने लिए रोजगार के नए मार्ग बना सकता है।

प्रदेश में कहीं-कहीं ओला-वृष्टि की सूचना मिलने पर संबंधित जिलों के कलेक्टर और कृषि उप संचालकों को मौका-मुआयना कर सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसान चिंतित न हों। ओला-वृष्टि से रबी फसलों को हुई क्षति की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ओला-वृष्टि से प्रभावित फसलों के सर्वे के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। गांवों में क्षतिग्रस्त फसलों का आंकलन पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाएगा। प्रभावित किसानों को आरबीसी-6 (4) के अंतर्गत राहत प्रदान की जाएगी। शिवराज सरकार किसान हितैषी सरकार है।

■ कमल पटेल, कृषि मंत्री

» किसान चिंतित न हों, ओला से फसलों को हुई क्षति की भरपाई सरकार करेगी

» प्रभावित फसलों की सर्वे के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी

किसान दे सकते हैं अपना सुझाव

मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अप्रैल 2020 में प्रारंभ किए गए कमल सुविधा केंद्र के माध्यम से अब तक हजारों किसानों की समस्याओं का निपटारा किया गया है। दूरभाष क्रमांक 0755-2558823 पर कॉल करके किसान फसल बीमा,आधार कार्ड और खाते की जानकारी में सुधार, कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। किसी योजना के लाभ से वंचित किसान अपनी परेशानियां या अन्य कोई भी कृषि संबंधी सुझाव दे सकते हैं।

मध्यप्रदेश में नवाचार आगामी खरीफ सीजन से लागू होगा

किसानों के लिए खजाना खोलेगी 'शिव' सरकार

विधानसभा का सत्र शुरू, दो मार्च को पेश होगा बजट

किसान सम्मान निधि के लिए रखे जाएंगे तीन हजार करोड़ रुपए

संवाददाता, भोपाल

शिवराज सरकार 22 फरवरी से प्रारंभ हुए विधानसभा के बजट सत्र में दो मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी। इसमें कृषि बजट का उल्लेख अलग से किया जाएगा। इसके 32 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का अनुमान है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है, उनकी घोषणाएं बजट सत्र में ही की जाएगी। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा जाएगा। वहीं, सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी बढ़ी राशि प्रस्तावित करने की तैयारी है। प्रदेश में कृषि बजट का उल्लेख अलग से करने की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही की थी। इस बार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है।

गांव-किसान पर फोकस

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। एक जिला-एक उत्पाद योजना इसी रणनीति का हिस्सा है। कस्टम हायरिंग सेंटर का विस्तार, कृषि उपज मंडियों की आय बढ़ाने के कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ई-मंडियां, भंडारण क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के प्रस्ताव बजट में शामिल किए गए हैं।

योजनाओं का बढ़ेगा दायरा

राजस्व विभाग भूमि प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार की गति को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। इस बार नई योजनाओं की घोषणा से ज्यादा जोर मौजूदा योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर रहेगा। किसानों को बिजली की सब्सिडी का भुगतान उनके खाते में करने संबंधी योजना की घोषणा हो सकती है।

इन विभागों के आएंगे अच्छे दिन

कृषि बजट (कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछुआ कल्याण, राजस्व, ऊर्जा, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, सहकारिता विभाग) 32 हजार करोड़ से ज्यादा होगा। 2018-19 में कृषि बजट 37,499 करोड़ था, जो 2019-20 में बढ़कर 46,550 करोड़ हो गया था। हालांकि, पुनरीक्षित अनुमान घटकर 37,953 करोड़ रह गया था। वर्ष 2020-21 के बजट में 26,264 करोड़ का प्रावधान किया था, जो अनुपूरक की राशि को मिलाकर 31 हजार करोड़ रुपए को पार कर चुका है।

मप्र के किसानों को भी होगा फायदा

20 परियोजनाओं पर लगी केंद्र की मुहर

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दो योजनाओं के तहत 363 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम और गुजरात में स्थापित होंगी। जबकि एपीसी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के तहत, मप्र, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान में 66.61 करोड़ की अनुदान सहायता सहित 250.32 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाले नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं 183.71 करोड़ के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इससे 8,260 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने और 36,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

सहकारी विपणन संघ की वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

किसान करा सकेंगे यूरिया की एडवांस बुकिंग

आनलाइन पहुंचेगी मांग, 20 % हिस्से की होगी बुकिंग

संवाददाता, भोपाल

हर साल सामने आने वाले यूरिया संकट से किसानों को निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक पहल करने जा रही है। इसके तहत किसान यूरिया की अग्रिम बुकिंग करा सकेंगे। किसान को राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। सूचना संबंधित सहकारी समिति के पास पहुंच जाएगी। परीक्षण में पात्रता सही पाए जाने पर किसान को एसएमएस से बुकिंग की सूचना दी जाएगी। यह नवाचार आगामी खरीफ सीजन से लागू होगा। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का दावा है कि किसानों के हित में इस तरह की पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में हर साल खरीफ और रबी फसलों के लिए 28 लाख टन यूरिया की जरूरत पड़ती है।

बुकिंग की सुविधा मिलेगी

खाद की मांग आती है और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है। इससे बचने के लिए सरकार ने तय किया है कि किसानों को अग्रिम बुकिंग की सुविधा दी जाए। इसमें किसान अपनी जरूरत की खाद पहले से ही आरक्षित करा लेगा। 4,529 सहकारी समितियां मार्कफेड से ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। समितियों को खाद की आपूर्ति मार्कफेड ही करता है। समितियां मांग भेजती हैं, जो सहकारी बैंकों के माध्यम से आती है।

कब और कौन सी खाद चाहिए

अब किसान मार्कफेड की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी भरेगा और बताएगा कि उसे कौन सी कंपनी की खाद किस अवधि में चाहिए। जैसे ही वह मांग करेगा, समिति प्रबंधक के लॉगिन में दिखाई देने लगेगा। समिति स्तर पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की जानकारी से उसकी मांग का मिलान करने के बाद अनुशंसा के साथ सहकारी बैंक को भेज दिया जाएगा। इस आधार पर खाद आरक्षित होगी।

सात दिन में उठानी होगी खाद

खाद उठाने के लिए सात दिन का समय मिलेगा ताकि मांग और आपूर्ति में तालमेल बना रहे। प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से हर साल 32-33 लाख किसान ऋण लेते हैं। इन्हें कुल साख सीमा का 65 फीसद हिस्सा नकदी और बाकी वस्तु के तौर पर मिला है। वस्तु के तौर पर ज्यादातर किसान खाद लेते हैं।

इनका कहना है

खाद बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदारी लाने के साथ किसानों को सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इसके लिए समिति स्तर पर उपलब्ध खाद का अधिकतम बीस फीसद हिस्सा ही आरक्षित किया जा सकेगा।

■ **उमाकांत उमराव,** प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग

पहली बार गोदाम संचालक सरकार के लिए खरीदेंगे गेहूं

» समर्थन खरीदी उपार्जन केंद्र के रूप में कराना होगा पंजीयन

» प्रति क्विंटल 27 रुपए गोदाम संचालकों को मिलेगा कमीशन

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में पहली बार गोदाम संचालक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकार के लिए गेहूं की खरीद करेंगे। इसके लिए उन्हीं गोदामों का चयन किया जाएगा, जिनमें कम से कम तीन हजार टन भंडारण क्षमता रिक्त होगी। इससे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर पड़ने वाला खरीद का अतिरिक्त भार कम होगा और परिवहन व भंडारण के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए गोदाम संचालकों को उपार्जन (खरीद) केंद्र के रूप में पंजीयन कराना होगा। यह प्रावधान उपार्जन नीति 2021 में किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिलने के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग अंतिम रूप दे रहा है। प्रदेश में 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22 मार्च से गेहूं की खरीद प्रारंभ होगी। किसानों की सुविधा के लिए 4,529 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें सहकारी समितियों के अलावा महिला स्वसहायता समूह और कृषक उत्पादक समूह शामिल हैं।

खरीदी की पर्याप्त व्यवस्थाएं

पहली बार गोदाम स्तर पर खरीद गोदाम संचालक ही करेंगे। यह काम अभी तक सहकारी समितियां करती रही हैं, लेकिन कार्यभार अधिक होने से लगातार मांग की जा रही थी कि विकल्प बढ़ाए जाएं। गोदाम स्तर पर सीमित खरीद होती है। जबकि, अधिकतर जगह पर खरीद की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। भंडारण के लिए उपार्जन केंद्रों से गेहूं परिवहन कर लाना होता है। इसमें समय और धन दोनों लगता है, इसलिए तय किया गया कि गोदाम संचालकों को ही खरीदने का अधिकार दे दिया जाए। इसके लिए उन्हें उपार्जन केंद्र के रूप में पंजीयन कराना होगा।

पंचायतों में होगी किसानों की सूची

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की सूची पहली बार पंचायतों में चस्पा की जाएगी। किसानों को ऑनलाइन भुगतान खाते में होगा। ऐसे किसान, जिन्होंने पिछले साल की तुलना में पचास फीसद अधिक क्षेत्र पंजीयन में दर्ज कराया है उनका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। चार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र, मोबाइल एप से पंजीयन कराने वाले, भू-राजस्व के रिकॉर्ड और पंजीयन में अलग-अलग नाम होने पर भी सत्यापन कराया जाएगा।

इनका कहना है

गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी। उपार्जन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। गोदाम स्तर पर अब संचालकों से खरीद कराई जाएगी। उन्हें प्रति क्विंटल 27 रुपए कमीशन दिया जाएगा। भंडारण के लिए राज्य भंडार गृह निगम से अनुबंध होगा। गोदामों का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति करेगी।

फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग

20 हजार किसान 49,600 हेक्टेयर जमीन करा चुके मुक्त

85,537 किसानों से 2580 करोड़ की वसूली अभी बाकी

बंधक भूमि मुक्त कराने का मौका देगी सरकार

फिर एकमुश्त समझौता योजना होगी लागू

संवाददाता, भोपाल

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को अपनी हजारों हेक्टेयर बंधक भूमि मुक्त कराने का मप्र सरकार एक मौका देने जा रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने एक बार फिर एकमुश्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल, बैंक बंद (परिसमापन) की प्रक्रिया में है और 85,537 किसानों से 2,580 करोड़ रुपए की वसूली होनी बाकी है। इस राशि को प्राप्त करने और किसानों को बंधक भूमि वापस लौटाने के लिए 2017 में समझौता योजना लाई गई थी। इसमें 20 हजार से ज्यादा किसानों ने 82.67 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर 49,600 हेक्टेयर भूमि को मुक्त करा लिया था। खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने वाला राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक खुद कर्ज की गिरफ्त में फंस गया और अंत तक उबर नहीं पाया।

किसानों ने दी सहमति

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से शासन की गारंटी पर ऋण लेकर इसने किसानों को दिया था, लेकिन वसूली नहीं हुई। शासन ने नाबार्ड का कर्ज तो अपने ऊपर ले लिया और उसे चुका भी दिया पर सहकारी बैंक का कर्ज फंसा है। इसे वसूल करने के लिए सरकार ने पिछले कार्यकाल में एकमुश्त समझौता योजना लागू की थी। इसमें तीन किस्तों में मूलधन लौटाने पर ब्याज पूरी तरह माफ करने प्रविधान था। 90 हजार से ज्यादा किसानों ने योजना से लिखित में सहमति जताई पर 20 हजार किसानों ने ही 82.67 करोड़ रुपए चुकाए। इससे किसानों को 213 करोड़ रुपए की ब्याज माफी मिली और 49,600 हेक्टेयर जमीन भी बंधक नहीं रही।

खरी नहीं उतरी योजना

योजना से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। अभी भी 38 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को किसानों से 2,580 करोड़ रुपए लेने हैं। इसमें मूलधन लगभग सात सौ करोड़ रुपए है। 50 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि बैंक के पास बंधक है। इसे छुड़ाने के लिए किसानों को कर्ज चुकाना होगा, जो बिना समझौता योजना के संभव नहीं है। एक बार फिर एकमुश्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। बैंक परिसमापन की प्रक्रिया में है पर किसानों पर कर्ज चढ़ा है। बैंक के पास बंधक भूमि को न तो बेचा जा सकता है न ही उस पर ऋण लिया जा सकता है। वसूली के लिए सहकारिता आयुक्त कार्यालय ने प्रस्ताव दिया है कि 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को यह जिम्मा सौंप दिया जाए।

वैज्ञानिकों का अनोखा शोध, ग्राफ्टिंग तकनीक का कमाल, किसानों को उम्मीद से बढ़कर मिल रहा लाभ

एक ही पौधे में उगाए आलू, बैंगन और टमाटर

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

हमारे देश के वैज्ञानिक नई-नई खोज करते रहते हैं, ना सिर्फ चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि आज हर क्षेत्र में हम आगे हैं। इसी प्रकार से जहां खेती के लिए पहले पुराने तरीके ही उपयोग में लाए जाते थे। वहीं अब नए-नए तरीकों से खेती की जा रही है। इसके साथ ही कृषि में कई प्रकार के शोध और अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को उम्मीद से बढ़कर फायदा मिल रहा है।

ऐसी ही एक खोज की है डॉ. आनंद बहादुर सिंह ने। उन्होंने वाराणसी के शहंशाहपुर में भारतीय किसान अनुसंधान संस्थान में शोध करके ग्राफ्टिंग तकनीक से इस प्रकार के पौधे उगाए हैं, जिसमें दो भिन्न-भिन्न सब्जियां एक ही पौधे में उगाई जा रही हैं। जैसे आलू और बैंगन एक पौधे में। टमाटर और बैंगन एक पौधे में उगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2013-14 से ग्राफ्टिंग टेक्निक की शुरुआत हुई

थी, जिससे ऐसे किसानों को बहुत फायदा मिला है जहां पर बारिश के मौसम में बहुत दिनों तक पानी भरा हुआ रहता है।

सब्जियों का नया शोध: डॉ. आनंद बहादुर सिंह वाराणसी के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक ही पौधे में दो सब्जियां उगाकर एक अनूठा शोध किया है। इसे ग्राफ्टिंग तकनीक कहा जाता है, जिससे टमाटर के पौधे में बैंगन के पौधे को कलम करके उन्हें एक ही पौधे में उगा रहे हैं। ये खास पौधे 24-28 डिग्री टम्प्रेचर में 85 फीसदी से ज्यादा नमी और बिना प्रकाश की नर्सरी में ही तैयार किए जा रहे हैं।

शहरों में के लिए उपयुक्त : इस तकनीक को विशेष रूप से शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है, जिन लोगों के पास पौधे उगाने के लिए स्थान की कमी होती है। क्योंकि आजकल शहरों में रहने वाले बहुत से लोग बाजार की केमिकल वाली सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए घर में ही थोड़ी जगह में सब्जियां उगाते हैं या फिर टेरेस गार्डन बनाकर अपने मनपसंद पौधे उगाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह तकनीक कारगर है।

ग्राफ्टिंग टेक्निक्स से किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही उनकी कमाई भी होगी। मैंने वर्ष 2013-14 से ही ग्राफ्टिंग टेक्निक पर काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो हमने आलू और टमाटर दोनों सब्जियां एक ही पौधे में उगाई फिर जब उससे अच्छी फसल प्राप्त हुई तो बैंगन और टमाटर को भी ग्राफ्टिंग से एक ही पौधे में उगा लिया। हमारी सारी टीम अब एक ही पौधे में आलू, टमाटर और बैंगन एक साथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक या दो साल में यह लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।

जगदीश सिंह, डायरेक्टर, भारतीय अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

ग्राफ्टिंग करने के 15-20 दिन के बाद पौधों को खेत में रोपा जाता है। फिर इसमें उचित मात्रा में उर्वरक और पानी डाला जाता है। साथ ही पौधे की कांट-छांट भी की जाती है। पौधे लगाने के 60 से 70 दिन के बाद इनमें फल लगना शुरू हो जाते हैं। हमें उम्मीद है ग्राफ्टिंग तकनीक से किसान लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा, जो गार्डनिंग के शौकीन हैं और अपने घर पर ही उगाए हुए फल और सब्जियां खाना पसंद करते हैं।

डॉ. आनंद बहादुर सिंह, वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

मध्यप्रदेश के हर गांव में खुलेगी गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री!

- गाय का गोबर बेरोजगारों को देगा रोजगार और रोकेगा पलायन
- गाय का गोबर अब बेरोजगारों के जीवन में बिखेरेगा खुशियों के रंग
- फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का एक तंत्र बन जाएगा
- सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपए कमाएंगे
- देश में फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जुटे
- गोबर से पेंट बनाने की एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख का होगा खर्च
- गांव में रोजगार मिलने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या होगी खत्म
- गाय के गोबर से बने और भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित, पेंट गंधहीन

अरविंद मिश्र, भोपाल

भारत गांवों का देश है। भारत की आधी से अधिक जनता गांवों में रहती है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने कहा था-असली भारत गांवों में बसता है। अधिकांश ग्रामवासी किसान होते हैं। गांवो में खेतों के अलावा पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय किए जाते हैं। पशुपालन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है और कृषि कार्य में सहायता मिलती है। पशुओं का गोबर खाद का काम करता है। इस लक्ष्य को लेकर मप्र को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी शिवराज सरकार जल्द ही केंद्र से अदेश मिलते ही एक और अनोखी पहले करने की तैयारी नजर आ रही है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो मप्र के सभी 52 जिलों, 293 नगर परिषद, 22,812 ग्राम पंचायत , 313 जनपद पंचायत में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खोली जाएंगी। इससे जहां एक ओर मप्र के किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर गौ-संरक्षण को भी बढ़ा मिलेगा। यही नहीं, गांवों में पशुपालन की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ेगा। सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों की संख्या में भी लगाम लगेगी। काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर श्रमिकों को अपने ही गांव-घर में काम मिल जाएगा। यानि पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। बस केंद्र सरकार से अनुमति मिलते ही मप्र में इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। दरअसल, हमारे समाज में गाय-भैंस के गोबर का कई तरह से इस्तेमाल होता है। गांवों में लोग वर्मी कम्पोस्ट या खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। उपले भी बना लिए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में गोबर बर्बाद हो जाता है। जबकि गोबर का कई और तरीकों से इस्तेमाल कर कमाई भी की जा सकती है। मप्र में अब ऐसा होने की पूरी संभावना है। गोबर की खपत के लिए हर गांव में फैक्ट्री खुलेगी। इस फैक्ट्री में गोबर से पेंट बनेगा। जिसे गोबर पेंट कहा जाएगा।

रुक जाएगा पलायन

केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को साकार करने की कवायद में जुटी हुई है। हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खुलवाने की तैयारी में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय खास प्लाने तैयार कर रहा है। जो मप्र सहित पूरे देश में लागू किया जाएगा। गोबर से पेंट बनाने के लिए एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख रुपए का खर्च आएगा। इससे हर गांव में रोजगार के बड़ी मात्रा में अवसर उपलब्ध होने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या खत्म हो जाएगी।

बाजार में आया गोबर से बना पेंट

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से तैयार गोबर से बना प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया था। यह पेंट इको फ्रेंडली है। पहला ऐसा पेंट है, जो विष-रहित होने के साथ फफूंद-रोधी, जीवाणु-रोधी गुणों वाला है। गाय के गोबर से बने और भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित, यह पेंट गंधहीन है। यह पेंट दो रूपों में उपलब्ध है- डिस्टेंपर तथा प्लास्टिक इम्यूलेशन पेंट के रूप में बाजार में आ चुका है।

गोबर से बना अनोखा पेंट लांच होने के बाद उसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। अभी जयपुर में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इतने आवेदन आए कि सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। साढ़े तीन सौ लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। इसकी पांच से सात दिनों की ट्रेनिंग होती है। ऐसे में हम ट्रेनिंग सुविधा बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री का संचालन करें। हर गांव में एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा रोजगार पैदा होगा।

नितिन गडकरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री

जयपुर यूनिट को मिली सफलता

एमएसएमई मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च 2020 से गोबर से पेंट बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को प्रेरित किया था। आखिरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जयपुर में स्थित यूनिट कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट ने इस तरह के अनोखे पेंट को तैयार करने में सफलता हासिल की। इस पेंट में सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातुओं का असर नहीं है।

किसानों की बढ़ेगी कमाई

गांबों में बने पेंट की बिक्री बढ़ने के बाद गांवों में गोबर की खरीद भी बढ़ेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपए कमाएंगे। अभी तक किसान गोबर का सिर्फ खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन, गांव-गांव पेंट की फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का भी एक तंत्र बन जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।

राज्यों से लिया जाएगा सुझाव

अभी मोदी सरकार इस पर मंथन कर रही है कि गांवों में लोगों को गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खोलने के लिए क्या-क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही कितना अनुदान दिया जाए, इस विचार-विमर्श चल रहा

है। इस योजना में ये भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी। यानि सरकारें क्या रियायत दे सकती हैं। पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है। ताकि फैक्ट्री खोलने के इच्छु लोगों को लोन लेने और उपकरण खरीदने में परेशानियों का सामना न करने पड़े। केंद्र का मुख्य फोकस यह है कि जब गांवों में फैक्ट्री का संचालन शुरू हो जाएगा तो गोबर पेंट के की बाजार में खपत कैसे बढ़ेगी। इस पर राज्य बार सरकारों से सुझाव भी मांगा जाएगा।

पंचायत की होगी अहम भूमिका

जब हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री शूरू हो जाएगी तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका और बढ़ जाएगी। चूंकि गांवों में पंचायत की देखरेख में ही संचालन किया जाएगा। विभाग यह भी देखेगा कि फैक्ट्री में स्थानीय लोगों का रोजगार मिल रहा है की नहीं। वहीं सरपंचों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। सरपंचों पर यह जिम्मा रहेगा कि फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को ही काम मिले। ताकि पलायन रुके। यही नहीं, गांव से फैक्ट्री में गोबर आए। किसानों को समय-समय पर उनके गोबर भुगतान हो।

अफसर जाएंगे गांव

गांवों में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री शुरू होने से पहले मंत्रालय में बैठने वाले अफसर गांवों ग्रामीणों के बीच नजर आएंगे। डेयरी (पशुपालन) विभाग के अफसर किसानों को उनकी आय बढ़ाने का प्रशिक्षण भी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि मवेशियों का आवारा न छोड़ें, बल्कि उनकी देखभाल करें और उन्हें समय-समय पर खाना-पानी दें। चाहे पशु दुधारू या न हो।

इनका कहना है

केंद्र सरकार की यह पहल सराहनीय है। गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री मप्र की हर पंचायत में होनी चाहिए। फैक्ट्र स्थापित होने से गौ-पालकों को की भी आय बढ़ जाएगी। जब आय बढ़ेगी तो संरक्षण भी होने लगेगा। मैं इसके लिए अपने जिला पंचायत से मांग करूंगा कि मप्र में सबसे पहले मेरी पंचायत में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री स्थापित हो। आज मुख्य समस्या है पलायन। इससे श्रमिक वर्ग का पलायन पूर्णत: रुक जाएगा। गांव में ही यदि लोगों को रोजगार मिलेगा तो पलायन जरूर रुकेगा। सरकार इस दिशा में यदि प्रयास कर रही है तो इसका फायदा जरूर लोगों को मिलेगा।

प्रमोद कुमार द्विवेदी, सरपंच, ग्राम पंचायत नीवी, जिला रीवा

गांवों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकारें वित्तीय सहयोग भी कर रही हैं। अगर पंचायतों में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट स्थापित होगी तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। गायों का संरक्षण होने लगेगा। पलायन रुक जाएगा। मप्र में यह व्यवस्था लागू होगी तो सबसे पहले मैं अपनी पंचायत में गोबर से पेंट बनाने की फैक्टी स्थापित कराऊंगा।

हीरा धाकड़, सरपंच, ग्राम पंचायत कामतौन, जिला रायसेन

खेत के रास्ते आत्मनिर्भर बनेगा मध्यप्रदेश

संजय माकवे
वरिष्ठ पत्रकार

पत्थर पर दूब कैसे उगाई जाती है यह केवल किसान ही जानता है। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल किसान पुत्र हैं, बल्कि स्वयं भी खेती किसानी करते हैं। इसलिए वे किसानों का मर्म भलीभांति जानते हैं। उन्होंने मप्र को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, वह खेत की पगडंडियों से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने खेती किसानी को हमेशा से अपनी प्राथमिकता में रखा है।

सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे क्रियान्वित कुछ ही लोग कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना संजोया है और अपने सपने को साकार करने के लिए खेती किसानी को प्राथमिकता में रखा है। अपने पूर्ववर्ती शासन काल में कृषि को मजबूत आधार देने के बाद उन्होंने अब 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया है। शिवराज सिंह ने चौथी पारी संभालते ही किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए खजाना खोल दिया। कृषि के क्षेत्र में शिवराज के नवाचारों को दूसरे राज्यों ने भी आत्मसात किया है। कोरोना संकट काल में भी किसानों को खाद, बिजली और सिंचाई के लिए पानी की सुविधाएं भरपूर मुहैया कराई। वहीं सरकार की सख्ती से बिचौलिए और खाद माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। जिन्होंने किसानों को ठगने की कोशिश की तो उन्हें कुचलने से भी सरकार पीछे नहीं रही। इसी का परिणाम है कि आज हमारे अन्नदाता पूरे मन से खेती किसानी में जुटे हैं और देश के साथ मप्र का भी नाम स्वर्ण अक्षरों दर्ज करा रहे हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, सरकार के प्रयासों में शामिल है। प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केंद्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केंद्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मप्र के किसानों को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों को मप्र शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार रुपए दो बराबर किश्तों में दिए जाना शुरू किया गया। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि मिल रही है। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को हुए नुकसान में राहत पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने सत्ता में आते ही बीमा योजना का लंबित प्रीमियम भरा और प्रभावित किसानों को फसल बीमा राशि दिलवाई गई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की गई। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना को पुन: चालू करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई गई। इसके लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि भी उपलब्ध करवाई गई, जिससे सहकारी बैंक किसानों को आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध करवा सकें। किसानों की आय बढाने के लिए बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य किया गया। प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020 तक लगभग 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गईं। प्रदेश में 19 वृहद, 97 मध्यम और 5344 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया एवं सिंगरौली जिलों में 1707 करोड़ की लागत से 24 हजार 364 भू-जल संरचनाओं का निर्माण कर सीमांत एवं लघु किसानों की 62 हजार 133 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित की गई। कोरोना काल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 653 जल- संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन जल संरचनाओं में रोजगार गारंटी योजनांतर्गत 1835 करोड़ से अधिक लागत के 1007 स्टॉप डेम, 4467 चेक डेम, 19 हजार कपिल धारा कूप, 2588 सार्वजनिक कूप, 1667 पर्कोलेशन टैंक, 14 हजार 907 हितग्राही मूलक खेत, 2365 सामुदयिक खेत तालाब तथा 4393 नवीन तालाब बनवाए गए। साथ ही 3115 बावड़ी, तालाब और सामुदायिक जल-संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा सामुदायिक टंकी निर्माण सहित 53 हजार 517 जल-संरचनाओं के कार्य किए गए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 237 करोड़ की लागत से 2697 खेत तालाब, 726 तालाब, 305 पर्कोलेशन तालाब, 299 चेकडेम, स्टॉप डेम और 109 नाला बंधान के कार्य किए गए। इन सभी जल संरचनाओं से जहां एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला। वहीं भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों को खेती में सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई बजट में निरंतर वृद्धि भी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नए प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानों में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किए जाने पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों से प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। कृषि अधोसंरचना विकास फंड में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिए आत्म-निर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। पिछले 10 माह में कृषि विकास एवं किसान-कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए गए हैं। किसानों के हित में मंडी नियमों में ऐतिहासिक सुधार भी किया गया है। मंडी टैक्स 1.50 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया गया। कृषि की लागत कम करने, उपादन बढ़ाने और उपज का सही दाम किसानों के दिलाने के लिए कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत किया जा रहा है। आगामी वर्षों मे एक हजार नए कृषि उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5 हजार रुपए की गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्ता के खाद-बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वर्ष किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराए जाने के बाद यूरिया का सरप्लस भंडारण रहा। नकली खाद-बीज बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित और निरस्त भी किए।

भ्रम और झूठ की राजनीति का विषवृक्ष है किसान आंदोलन

प्रो. रसाल सिंह

तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब तीन महीने से कुछ किसान संगठनों का आंदोलन जारी है। यह आंदोलन एक तरह से भ्रम और झूठ की राजनीति का विषवृक्ष है। कई विपक्षी दल इसे सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समय भी विपक्ष ने ऐसा ही भ्रमजाल फैलाया था। उस समय जिस प्रकार मुसलमानों को नागरिकता छीनने और 'देश निकाले' का डर दिखाया गया था, ठीक उसी प्रकार इस बार किसानों को जमीन छीनने और कॉरपोरेट का बंधुआ मजदूर बनने का डर दिखाया जा रहा है। किसान संगठनों और विपक्ष को अन्नदाताओं को बहकाने का अवसर इसलिए मिला, क्योंकि सरकार सही समय पर किसानों को सही बात बताने में नाकाम रही। संपर्क और संवाद की कमी इस आंदोलन की उपज का एक बड़ा कारण है। जिन दो-तीन बिंदुओं पर विपक्ष को किसानों को भड़काने और भरमाने का मौका मिला, उनमें केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और सरकारी खरीद-व्यवस्था की समाप्ति, बढ़ कॉरपोरेट घरानों द्वारा ठेके पर किसानों की जमीनें लेकर उन्हें हड़प लेने तथा किसानों को बंधुआ मजदूर बना लेने की आशंका और विवाद होने की स्थिति में न्यायालय जाने की विकल्पहीनता का भय खड़ा किया गया।

भोले-भाले किसान पंजाब की वर्चस्वशाली और आढ़तिया लॉबी के दुष्प्रचार के भी शिकार हो गए और उनके बहकावे में आकर घर से निकल पड़े। दरअसल इन कानूनों से नुकसान बिचौलियों और आढ़तियों को होना है। इसलिए उन्होंने इन कानूनों को रद्द कराने के लिए सारी शक्ति और संसाधन झोंक डाले। पंजाब की कांग्रेस सरकार और आढ़तिया लॉबी द्वारा सुलगाई गई यह आग धीरे-धीरे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में भी फैल गई। बिजली संशोधन विधेयक, पराली जलाने पर दंडात्मक कार्रवाई वाले कानून और गन्ना किसानों की लंबे समय से बकाया राशि के भुगतान में चीनी मिलों द्वारा की जा रही आनाकानी आदि कारणों ने इस आग में घी का काम किया। हालांकि 26 जनवरी की घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना नैतिक बल खो दिया है और इसी कारण उसका चक्का जाम और रेल रोको का आयोजन सीमित असर वाला ही साबित हुआ। किसान नेताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी घेराबंदी ने दिल्ली और आसपास के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम मुश्किलें खड़ी कर दी है। किसान नेताओं को इन निर्दोष नागरिकों की परेशानियों की भी चिंता करनी चाहिए और अपनी जिद छोड़नी चाहिए।

सरकार और धरनारत किसानों के बीच करीब एक दर्जन बार वार्ता हो चुकी है। केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को तत्काल रद करने के अलावा किसानों की तमाम मांगें मान ली हैं। इसके साथ ही सरकार ने समझौते और समाधान के लिए गंभीरता दिखाते हुए तीनों कानूनों को 18 महीने तक स्थगित रखने और इस बीच आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाने का भी वादा किया है।

फिर देश का अन्न भण्डार भरेगा हमारा मध्यप्रदेश

डॉ. आनन्द शुक्ल

देश का अन्न भंडार भरने की तैयारी मध्यप्रदेश ने एक बार फिर शुरू कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चैहान के कुशल मार्गदर्शन में कृषि अधोसंरचना को लेकर शुरू किए गए सुधार कार्य, सिंचाई में निरंतर हो रही वृद्धि तथा किसानों की दी जा रही सहूलियत का परिणाम है कि मध्यप्रदेश में अब रबी और खरीफका उपार्जन विगत वर्षों की तुलना में काफी बढ़ गया है। बीते वर्ष 2020 में कोविड-19 जैसी विकट और प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी मध्यप्रदेश के किसानों ने रिकार्ड गेहूं का उत्पादन किया। शासन स्तर पर की गई तैयारियों का परिणाम था कि देश के कुल उपार्जन का एक तिहाई अन्न मध्यप्रदेश से ही उपार्जित किया गया। आंकड़ों की बात करें तो 1 करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अकेले मध्यप्रदेश से ही किया गया था। इस रिकार्ड उत्पादन के दम पर मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन के मामले में देश का अग्रणी राज्य बना। इस उपलब्धि के पीछे लगभग 17 लाख किसानों की महनत है। सरकार ने भी किसानों के खातों में 24 हजार करोड़ रुपए सीधे जमा किए थे।

कृषि को लेकर जिस प्रकार की दूरगामी नीति और सुधार के कार्यक्रम मध्यप्रदेश में चलाए जा रहे हैं उससे एक बार फिर यह बात तय हो गई है कि इस वर्ष भी गेहूं के उपार्जन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्य बन कर रहेगा। बीते वर्षों में लगभग 4500 केन्द्र उपार्जन के लिए बनाए गए थे। इसके साथ ही किसानों को तीन प्रकार से फसल बेचनें की सुविधा भी दी गई थी। यह किसान पुत्र शिवराज की दूरदर्शिता का परिणाम था। फसल बेचने की सुविधा में किसान अपनी उपज उपार्जन केन्द्र पर ले जा सकता है, मंडी द्वारा अधिकृत प्राईवेट खरीद केन्द्रों पर और मण्डी में पंजीकृत व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से भी अपनी फसल बेच सकता है। यह सभी व्यवस्थाएं पुन: किसानों के लिए संचालित हो रही हैं। उपार्जन के समय दो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है उसका परिवहन और भंडारण। परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रकों की व्यवस्था तथा भंडारण के लिए 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त की व्यवस्था भी पहले से ही मौजूद है। बारदाने और साईलो बैग की भी व्यवस्था शासन ने पहले से ही कर रखी है। इस समूची प्रक्रिया में गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार 6 जिलों में महिला स्व: सहायता समूहों को भी रबी उपार्जन की अनुमति दे चुका है। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। अगले महीने से खरीदी से पूर्व उन्हें एसएमएस के माध्यम से अग्रिम सूचना भेजने का काम भी शुरू हो जायेगा, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। जानकारों का कहना है कि मध्यप्रदेश में पैदावार में हो रही दिनो दिन वृद्धि का सबसे बड़ा कारण शिवराज की दूरदर्शी नीति है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था तथा फीडर सेपरेसन के माध्यम से जो काम खेती के लिए किया गया है उसका परिणाम है कि अब मध्यप्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनकर उभरा है। इन सबसे बावजूद इस वर्ष सबसे अहम बात यह है कि रबी की बोवनी से लेकर अभी तक मौसम की अनुकूलता बनी हुई है। प्रकृति भी साथ दे रही है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने चना और सरसों जैसे उत्पादन को भी गेहूं के साथ-साथ उपार्जित करने की व्यवस्था कर दी है। पूर्व के दिनों में यह व्यवस्था नहीं थी। गेहूं उपार्जन के बाद सरसों और चना की खरीदी होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इसका सीधा लाभ आर्थिक दृष्टि से किसानों को मिल सकेगा।

सीएम शिवराज ने हमेशा कहा है कि प्रदेश का अन्नदाता हमारे लिए भगवान है और हम उसके खेतों को पानी, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली, खेती की लागत को कम करने में अधिक से अधिक सहूलियत तथा आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। खेती में हो रहे दिनो दिन सुधार के चलते मध्यप्रदेश के किसानों की स्थिति आने वाले दिनों में लाभप्रद साबित होगी। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि खेती को लाभ का धंधा बनाने या किसानों की आय दोगुनी करने की शुरूआत मध्यप्रदेश से ही हो सकती है। इसलिए यह कहना तर्क संगत है कि मध्यप्रदेश आने वाले दिनों में उपार्जन और आय दोगुनी करने की दृष्टि से भी देश के अन्य राज्यों में अग्रणी होगा और कृषि के लिए एक रोल मॉडल भी बनेगा। इस मामले में शिवराज का संकल्प अब जमीन पर साकार होता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि प्रदेश का किसान और आम आदमी सरकार के इन प्रयासों के साथ हमकदम होते हुए आगे बढ़े और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में शत-प्रतिशत योगदान दे।

» जिद-जुनून से वृद्ध किसान ने कायम की थी मिसाल

» किसान से मिली प्रेरणा ने बदली पूरे गांव की तस्वीर

» ड्रिप इरनगेशन सिस्टम बना बदलाव का जरिया

खुमान की तकनीक से किसान चमका रे अपनी तकदीर

दीपेंद्र तिवारी, देवरी/सागर

सागर जिले की देवरी तहसील का एक ऐसा गांव जहां के किसान आज से करीब 10 साल पहले तक एक ढर्रे पर सोयाबीन, गेहूं, चना जैसी पारंपरिक फसलें लेने में ही विश्वास रखते थे। बेरोजगारी काट रहे युवा गांव की चैपालों पर ताश खेलते, बीड़ी का धुआं उड़ाते दिख जाते, कुछ समझदार प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रोजी-रोटी की तलाश में शहरों की खाक छानते घूम रहे थे। लेकिन एक वृद्ध किसान की दूरदर्शी सोच और दृढ़ निश्चय ने आज इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। उसने अपनी जिद-जुनून और जज्बे के सामने किस्मत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर जिस उम्र में लोग अपने दायित्वों से मुक्त की सोचते हैं, उस उम्र में बदलाव की बयार का यह किस्सा ग्राम कुसमी में वर्ष 2011 से शुरू हुआ। करीबन 52 वर्ष की उम्र में स्व. खुमान सिंह लोधी को सबसे पहले ड्रिप इरीगेशन के बारे में एक सरकारी योजना के तहत जानकारी मिली। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को समझने के लिए स्व.खुमान सिंह ने अधिकारियों की मदद से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को अपना चुके किसानों से मुलाकात की और पूरी प्रक्रिया समझने के बाद उन्होंने इसे अपनाने का मन बना लिया।

50 डिसमिल जगह से की शुरुआत

खुमान सिंह के पुत्र जगदीश बताते हैं की ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से सब्जी उगाने की शुरुआत उनके पिता ने अपनी बंजर पड़ी जमीन के 50 डिसमिल हिस्से से की थी। जमीन में ड्रिप सिस्टम के पाइप बिछाते वक्त कई किसानों ने इसे स्व. खुमान सिंह का पागलपन तक कहा, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। गांव के किसानों का तर्क था कि जहां खुला पानी देने के बाद गेहूं और चना जैसी पारंपरिक फसलें लेने में परेशानी आती है वहां बूंद-बूंद पानी से क्या होगा। इस सबके विपरीत खुमान सिंह किसानों को ड्रिप सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। 2019 में 59 वर्ष की उम्र उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी दूरदर्शिता का असर अब इस पूरे इलाके में दिखने लगा है। साल दर साल कुसमी के साथ ही साथ क्षेत्र के किसान ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को अपना रहे हैं।

इनका कहना है

पहली ही बार में स्व. दादा खुमान सिंह की बंजर जमीन के मात्र 50 डिसमिल हिस्से में मिर्च की शानदार पैदावार हुई। करीब साल भर में मिर्च की इस फसल से उन्हें दो लाख रुपए की आय हुई। इसके बाद तो गांव के ही नहीं आसपास के कई किसानों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का मन बनाते हुए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को अपना लिया।

दयाराम रजक, किसान, कुसमी

साल भर भारी मात्रा में सब्जियों की पैदावार होने से आमतौर पर उत्पादकों को सब्जी बेचने बाजार नहीं जाना पड़ता है। जिले के साथ ही आसपास की छोटी-बड़ी सभी सब्जी मंडियों से लेकर दूसरे जिलों जैसे दमोह,जबलपुर, रायसेन, भोपाल और नरसिंहपुर तक के व्यापारी खरीदी के लिए गांव ही पहुंच जाते हैं।

परसादी कुर्मी, किसान

आमतौर पर बैगन, टमाटर और मिर्च का उत्पादन लेने वाले क्षेत्र के किसान मौसम के मुताबिक गिल्की, करेला, लौकी, ककड़ी और शिमला मिर्च की भी फसलें उगाते हैं। सब्जी की फसल लेने के लिए हर वर्ष कुछ नए किसान तैयार होने से उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ रहा है। अब किसान गर्मी में यहां तरबूज उगाने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं।

सुखदेन सिंह पटेल, किसान

सब्जी का उत्पादन कम जमीन में अधिक लाभ कमाने का बेहतर तरीका है। उनके परिवार में सदस्यों की संख्या के हिसाब से जमीन काफी कम है और कमाई का दूसरा कोई जरिया भी नहीं है। ऐसे में पारंपारिक के साथ ही सब्जी जैसी नकदी फसलों का उत्पादन उन्हें काफी सहारा देता है।

मनोहर कुर्मी, सब्जी उत्पादक

अब रोजगार की चिंता नहीं

सब्जी उत्पादन से पूर्व क्षेत्र के छोटे किसानों का कृषि कर परिवार चलाना कठिन था। ऐसे में कई किसान और उनके परिजन रोजगार की तलाश में शहरों का रूख कर लिया करते थे। आठ एकड़ जमीन के मालिक कैलास रजक बताते हैं कि सब्जी उगाने से पूर्व मैं भी भोपाल में सुरक्षाकर्मी के रूप में 10 हजार रुपए महीने की आमदनी पर काम किया करता था।

लहसुन की पैदावार

कुसमी से सटे ग्राम मोकला निवासी किसान पवन पटेल कहते हैं कि फिलहाल हम पारंपरिक फसलों के साथ लहसुन की पैदावार ले रहे हैं। हालांकि इस वर्ष से मैंने भी टमाटर, बैगन सहित अन्य सब्जियों का उत्पादन करने की तैयारी कर ली है। पारंपरिक फसलों के साथ ही नकदी फसलें लेने से किसान काफी लाभ कमा रहे हैं।

सौर ऊर्जा का उपयोग

ड्रिप इरीगेशन से सब्जी उत्पादन कर मिसाल बने कुसमी सहित आसपास के किसान सौर ऊर्जा का उपयोग करने में भी पीछे नहीं हैं। कुसमी सहित आसपास के गांव सिंगपुर गुंजन, मोकला, सुना, सूरादेही, डुंगरिया, डोंगर सलैया और परासिया के किसान ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से जहां पानी का सही उपयोग कर रहे हैं।

रसायन मजबूरी, जैविक जरूरी

मूल रूप से लहसुन और प्याज की खेती करने वाले डोंगर सलैया निवासी किसान कमलेश पटेल जैविक खाद और कीटनाशक को सबसे बेहतर मानते हैं। वे कहते हैं कि रसायन खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करना किसानों की मजबूरी बन गई है। जबकि रसायन की जगह गोबर की खाद से सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है।

योजनाओं का मिल रहा लाभ

सरकारी योजनाओं के सवाल पर युवा किसान अनूप लोधी का कहना है कि समय-समय पर उद्यानिकी विभाग की ओर से उन्हें मार्ग दर्शन मिलता रहता है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को सौर विद्युत प्रकल्पों पर भी काफी छूट मिलती है।

निकरा परियोजना अंतर्गत कृषक प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन

रतलाम। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम द्वारा संचालित जलवायु समुर्थान कृषि में नव प्रवर्तन परियोजना अंतर्गत ग्राम दौलतपुरा में कृषक प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. सर्वेश त्रिपाठी ने कृषकों को कृषि की नई-नई तकनीकों एवं वर्तमान में हो रहे मौसम परिवर्तन के बारे में अवगत किया। साथ ही गेहूं की प्रजाति एचआई 1605 में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उपस्थित डॉ. चतरा राम कांटवा, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) ने वर्तमान क्षेत्र के अनुसार प्रचलित व उपयुक्त प्रजातियों एवं उनकी बीज दरों व फसल विन्यास एवं उर्वरकों की मात्रा व पकने की अवधि पर विस्तृत जानकारी दी।

-बैंगलोर में आयोजित चार दिवसीय बागवानी मेले में स्टॉल को मिला दूसरा पुरस्कार

मंडला के कोदो-कुटकी को अब मिली राष्ट्रीय पहचान

सैय्यद जावेद अली

मंडला। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर (कर्नाटका) में चार दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला में मंडला जिले के उत्पाद कोदो-कुटकी की कुकीज के स्टॉल को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया।

जिले से कृषि विज्ञान केंद्र मंडला और किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंडला के संयुक्त तत्वाधान में तेजस्विनी महिला संघ द्वारा स्टॉल कलेक्टर हर्षिका सिंह, कृषि तकनीकी

अनुसंधान संस्थान (अटारी) क्षेत्र 9 के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह, संचालक विस्तार सेवाएं जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर, डॉ. ओम गुप्ता के मार्ग दर्शन और कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के डॉ. विशाल मेश्राम, कृषि विभाग से आरके मंडाले की उपस्थिति में महिला संघ से जमीला खान, प्रमिला धुर्वे और यामोद जंघेला द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय स्तर के मेले में सर्वोत्तम स्टॉल श्रेणी में मंडला जिला द्वारा लगाए गए स्टॉल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होने से जिले का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और जिले के उत्पाद कोदो, कुटकी को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। मंडला कलेक्टर हर्षिका के द्वारा योजना भवन में सभी स्टॉल संचालन में जुड़े सदस्यों कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम उपसंचालक, एसएस मरावी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आर के मंडाले किसान कल्याण और तेजस्विनी महिला संघ से जमीला खान, प्रमिला धुर्वे और यामोद को सम्मानित किया गया।

विदेश में बढ़ी रतलाम के लहसुन की डिमांड

» दिल्ली, मुंबई, मद्रास जैसे महानगरों में धाक

» लहसुन की खेती में किसान निकले अव्वल

» अन्नदाता जैविक पद्धति से कर रहे खेती

अमित निगम, रतलाम

मप्र के किसान अब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। खेती-किसानी नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर देश के साथ राज्य का भी नाम रोशन कर रहे हैं। रतलाम में स्ट्राबेरी, मटर, अंगूर, अमरूद की खेती के साथ ही लहसुन की खेती में भी जिले के किसान अव्वल हैं। जिले में प्रतिवर्ष ढाई लाख मीट्रिक टन से अधिक लहसुन का उत्पादन हो रहा है। ज्यादातर किसान जैविक पद्धति से खेती कर रहे हैं। इस वजह से लहसुन की विदेशों में भी विशेष मांग हो रही है। प्रदेश में भी सबसे बेहतर क्वालिटी का लहसुन रतलाम का ही माना जाता है, जो देश के दिल्ली, मुंबई, मद्रास जैसे महानगरों में धाक जमाए हुए है। तीस हजार हेक्टेयर में हो रही लहसुन की खेती से 25 हजार किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आत्म निर्भर मप्र अभियान के तहत भी लहसुन के उत्पादन पर ध्यान दिया जा रहा है। जिले के पिपलौदा, जावरा और रतलाम ब्लाक में सबसे अधिक किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। रबी सीजन में उत्पादन अधिक होता है।

मलेसिया में भी मांग

व्यापारी नीलेश बाफना के अनुसार रतलाम में होने वाली उंटी लहसुन की गांठ मजबूत होती है। औषधि गुण व स्वाद में बेहतर होने के कारण सउदी अरब, बंगलादेश और मलेशिया में रतलाम के लहसुन की अच्छी मांग है।

एक हेक्टेयर में 90 क्विंटल

जिले के पिपलौदा के लहसुन उत्पादक किसान राजेश पाटीदार बताते हैं कि मल्चिंग पद्धति से लहसुन की जैविक खेती हो रही है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। इसकी सप्लाई देश के बड़े शहरों के अलावा विदेशों में भी होती है। एक हेक्टेयर में 90 क्विंटल तक उत्पादन हो रहा है। दो हेक्टेयर में हमें हर सीजन 190 क्विंटल तक उत्पादन मिल रहा है। खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है।

इनका कहना है

रतलाम जिले में लहसुन उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा विदेश जा रहा है। हर सीजन में ढाई लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन हो रहा है। औसतन लहसुन 60 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। यहां के किसान सीधे दिल्ली, मुंबई, मद्रास जैसे शहरों की मंडी में लहसुन भेजते हैं। वहां से आयात-निर्यात करने वाले व्यापारी विदेश भेज रहे हैं।

पीएस कनेल, उपसंचालक, उद्यानिकी विभाग, रतलाम

देशभर में मालवा का मीठा प्याज बना पहली पसंद

संवाददाता, उज्जैन

साक-सब्जियों के भाव जहां एक ओर लोगों का जायका बिगाड़ रहे हैं। साथ ही जेब पर भारी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देशभर में मप्र के मालवा का मीठा प्याज लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। वर्तमान में आवक कम होने से भाव में तेजी बरकरार है। यह थोक में 35 से 38 रुपए किलो बिक रहा है। जबकि आम उपभोक्ताओं को 45 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। देश के बार और मप्र के अलावा दूसरे राज्यों में काफी मांग है। थोक सब्जी मंडी प्रतिदिन 1000 कट्टे की आवक हो रही है। गौरतलब है कि जिले में प्याज की खेती के प्रति किसानों का रुझान काफी बढ़ा है। इस साल 15 हजार 706 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बोवनी की गई है। जो कि अगले माह बाजार में आने लगेगा। उत्पादन करीब 3.5 लाख टन की संभावना है। इस क्षेत्र का प्याज प्रदेश के बाहर काफी मात्रा में बिकने के लिए जाता है।

तीन राज्यों में व्यापार: उज्जैन मंडी से ही लाखों रुपए का कारोबार होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में काफी व्यापार होता है। वर्तमान में आवक कमजोर होने से प्याज के भाव में तेजी बनी हुई है। थोक मंडी में अभी यह 35 से 38 किलो बिक रहा है। आम उपभोक्ताओं को प्याज 50 रुपए किलो में खरीदना पड़ रहा है।

आवक बढ़ने से गिरेगा भाव : कई बार सीजन में बंपर आवक के चलते किसानों का प्याज 4 से 5 किलो तक बिक जाता है। ऐसे में किसानों को उत्पादन की लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। किसानों के अनुसार इस बार प्याज का उत्पादन व क्वालिटी काफी अच्छी है। अगले माह नए प्याज की आवक होने की संभावना है। मंडी में रोजाना 15 से 20 हजार कट्टे बिक्री के लिए आने लगेंगे। आवक बढ़ने के बाद प्याज के भाव में कमी आ सकती है।

» वर्तमान में आवक कम होने से भाव में तेजी कायम

» मंडी में थोक में 35 से 38 रु. किलो बिक रहा प्याज

देशभर में स्वाद को चटख बनाएंगे खरगोन के रसीले टमाटर

- अब जायकेदार टोमेटों पल्प और पेस्ट के लिए भूमि तैयार
- पल्प एंड पेस्ट बनाने वाली कंपनी ने किए सफल ट्रॉयल

संवाददाता, खरगोन

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की उपजाऊ भूमि से पैदा होने वाले जायकेदार और रसीले टमाटर का पल्प व पेस्ट अब पूरे प्रदेश सहित देश में रंग जमाएगा। यहां से न सिर्फ टमाटर का पल्प बल्कि मिर्च का पेस्ट भी बनेगा। इतना ही नहीं, टमाटर मिर्च के अलावा अमरूद, पपीता और आम के भी स्वादिष्टि और जायकेदार खट्टे-मीठे उत्पाद तैयार होंगे। इसके लिए फ्रूटेक्स इंडस्ट्रीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। कंपनी के पार्टनर शशांक भदौरा ने बताया कि खरगोन में मिर्च, अमरूद, पपीता और मैंगो प्रमुखता के साथ मिलता है। इसके अलावा टमाटर के पल्प के लिए भी हमें उपयोगी टमाटर तैयार करने थे। इसके लिए बरूड़ के किसानों के खेतों में ट्रॉयल किए हैं, जो वास्तव में सुखद परिणामों वाला रहा है। हालांकि यहां पहले से ही किसान टमाटर की खेती करते रहे हैं। लेकिन पल्प व पेस्ट के लिए हमें एक भिन्न किस्म के

टमाटर चाहिए होते हैं, जिसके आसानी से पल्प बनाए जा सके। हमारी कंपनी दिसंबर 2021 से अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर देगी।

किसानों ने की कांट्रेक्ट फॉर्मिंग: फ्रूटेक्स इंडस्ट्रीज ने अपना प्लांट प्रारंभ करने से पूर्व बरूड़ के पांच किसानों के खेतों में एक-एक एकड़ रकबे में कांट्रेक्ट फॉर्मिंग शुरू की। राजेश कुमरावत ने बताया कि कंपनी ने एक एकड़ में पौधे प्रदान की। इस किस्म में 70 दिनों से ही फ्रूटिंग शुरू हो गई। इसके लिए हम किसानों को 4-4 किश्तों में 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदान की है। इसके अलावा अनुबंध के अनुसार 4 रुपए प्रति किलो का लाभ भी प्रदान करेगी।

अब नहीं फेंकना पडेंगा टमाटर: बरूड़ के ही युवा किसान विक्ती कुमरावत बताते है कि हम बरसों से टमाटर की फसल ले रहे हैं, जिसमें बांस-बल्ली का भरपूर उपयोग होता है। इससे किसानों की फसल लागत बढ़ जाती है, लेकिन जापानी किस्म के टमाटर में बांस-बल्ली की जरूरत नहीं होती। इस कारण किसानों के लिए बेहद लाभकारक हो सकता है। साथ ही हमारे जैसे टमाटर व मिर्ची के साथ-साथ अमरूद, पपीता व मैंगो उत्पादक किसानों के लिए खुशी की बात है कि जिले में ही इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्रारंभ होगी। अब किसानों को अपने टमाटर की फसल कम कीमत के कारण फेंकना नहीं पड़ेगी। रामेश्वर कुमरावत, विक्की कुमरावत, संदीप कुमरावत, राजेश कुमरावत व महेश कुमरावत के खेतों में एक-एक एकड़ में ट्रायल किए गए हैं।

यूनिट हुआ भूमिपूजन: लंबे समय से जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी के अंतर्गत इंड्स मेगा फूड पार्क निमरानी में दो एकड़ रकबे में फ्रूटेक्स इंडस्ट्रीज ने भूमिपूजन किया है।

इनका कहना है

यह यूनिट मध्य भारत की सबसे बड़ी यूनिट होगी। जहां पल्प व पेस्ट बनकर तैयार होगा। जिसको किसी प्रिजरवेटिव मिलाए बिना लंबे समय तक पैकेजिंग कर बाजार में बेचा जाएगा। ईसेप्टीक पैकेजिंग विधि से यहां बनने वाले प्रोडक्ट को सहेज कर रखा जाएगा। इस यूनिट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान संपदा योजना से 5 करोड़ रुपए सब्सिडी भी दी जाएगी। यूनिट का 100 टन प्रतिदिन का उत्पादन होगा। यहां मौसम आधारित कार्य लगातार किए जाएंगे।

शशांक भदौरा, पार्टनर, फ्रूटेक्स इंडस्ट्रीज, कंपनी

उद्यानिकी फसलों से किसान होंगे खुशहाल

» उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरत सिंह कुशवाह ने कहा

» एक उत्पाद एक जिला के तहत मिलेगा फूड प्रोसेसिंग का लाभ

» परंपरागत खेती की जगह आधुनिक खेती दिया जाए बढ़ावा

संवाददाता, रीवा। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने तथा विस्तार करने के लिए प्रदेश के 20 आदर्श विकासखंडों का चयन किया गया है। इसमें रीवा जिले के रीवा विकासखंड का चयन आदर्श विकासखंड के रूप में किया गया है। चयनित आदर्श विकासखंडों में सब्जी विस्तार, फल विस्तार, मशाला विस्तार, औषधि विस्तार किया जाएगा। इससे किसान के जीवन स्तर में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए जरूरी है कि वे रबि और खरीफकी खेती के साथ ही उद्यानिकी फसलों को अपनाएं। यह बात प्रदेश उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण तथा नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भरत सिंह कुशवाह ने रीवा में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कृषक प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ के दौरान कही। इस दौरान रीवा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित उद्यानिकी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर इलैयाराजा टी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, संयुक्त संचालक उद्यान जेपी कोलेकर, सहायक संचालक उद्यान योगेश पाठक सहित प्रगतिशील किसान मौजूद थे।

धर्मजय सिंह का गुलाब हवाई जहाज से जा रहा बाहर

राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा जिले में उद्यानिकी फसलों के विस्तार के लिए खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की जाए ताकि किसान समृद्धि शाली बनें। आधुनिक तकनीक एवं खेती अपनाकर रकरी ग्राम के प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह करोड़ों रुपए का टर्न ओवर कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित गुलाब हवाई जहाज से बाहर भेजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि रीवा में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया जाए।

सुंदरजा के लिए चुना गया रीवा

मंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत रीवा जिले का चयन सुंदरजा आम के लिए किया गया है। किसानों को इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग का लाभ दिया जाएगा। आगे चल कर जो किसान उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करेंगे उन्हें चेन फेसिंग के लिए क्रमश: 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किसान उद्यानिकी फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर बने। उद्यान विभाग नर्सरी में किसानों की मांग के अनुरूप ही पौधों का उत्पादन करे।

कृषि के क्षेत्र में क्रांति आयी

वहीं भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि समृद्ध शाली बनने के लिए आवश्यक है कि किसान परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती को अपनाएं। रीवा जिले में सिंचाई के लिए पानी और बिजली मिलने से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आयी है। उद्यानिकी फसलों को अपनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए अनुदान दिया जाए तो किसान इसे शीघ्र अपनाएंगे।

किसानों को मिले अनुदान

विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि उद्यानिकी फसलों को अपनाकर किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों को चैन फसिंग के लिए अनुदान दिया जाए। जिला पंचायत के कृषि समिति के सभापति ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

मऊगंज में लहलहा रहा 'पूसा मंगल' गेहूं

» तीन से चार पानी में एचआई 8713 गेहूं की फसल तैयार

» एक एकड़ में 22 से 24 क्विंटल उत्पादन की उम्मीद

» स्थानीय किसानों के आकर्षण का केंद्र बनी फसल

» कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर किया दवा का छिड़काव

संवाददाता, भोपाल/रीवा

उन्नत एवं नई-नई किस्म की खेती-किसानी को लेकर चर्चित प्रगतिशील किसान अनिल कुमार मिश्र एक बार फिर चर्चा में हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की तहसील मऊगंज के ग्राम मऊबगदरा की। किसान ने पहली बार अपने खेत में पूसा मंगल (एचआई 8713) किस्म के गेहूं की बोवनी की है। गेहूं की यह फसल स्थानीय किसानों के आकर्षण का केंद्र बनीं हुई है। पूसा मंगल गेहूं एक हरफनमौला किस्म है जो रोग प्रेतिरोधक होती है। हालांकि इसका कुछ दाना हल्का और कुछ रंग का होता है जिस वजह से यह भद्दा दिखता है। लेकिन इसके पोषक तत्वों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसके पौधे की लंबाई 80 से 85 सेंटीमीटर होती है। 120 से 125 दिन में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है। इसकी बोवनी 15 से 25 नवंबर तक उचित मानी जाती है। इसमें 3 से 4 पानी सिंचाई होती है। इसका उत्पादन एक एकड़ में 22 से 24 क्विंटल और हेक्टेयर में इसका उत्पादन 55 से 60 क्विंटल तक होता है।

फसल लगभग तैयार

किसान अनिल कुमार मिश्रा ने 'जागत गांव हमार' से चर्चा के दौरान बताया कि 9 नबंवर को पूसा मंगल (एचआई 8713) किस्म के गेहूं की करीब डेढ़ एकड़ में बोवनी की थी। अब फसल लगभग तैयार हो गई है। भारी मिट्टी होने की वजह से पांच पानी की सिंचाई करनी पड़ी। इस किस्म की पहली बार बोवनी की है। अब फसल को सींचने की जरूरत नहीं है। मार्च के पहले सप्ताह में फसल काटने लायक हो जाएगी। पूसा मंगल (एचआई 8713) गेहूं का बीज मऊगंज कृषि विभाग से लिया था।

कैसे तैयार हुई फसल

बोवनी के बाद 15-18 दिन में पहली सिंचाई अवस्था-चंदेरी जड़ें निकलते समय, दूसरी सिंचाई 35-40 दिन बाद कल्ले निकलते समय, तीसरी सिंचाई 50-60 दिन बाद गांठें निकलते समय, चौथी सिंचाई 75-80 दिन बाद गेहूं में फूल आने के पूर्व और पांचवीं सिंचाई 95-100 दिन बाद दुग्ध अवस्था में की गई।

गेहूं की खासियत

पूसा मंगल (एचआई 8713) किस्म के गेहूं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बालियों को पक्षी भी नहीं काट पाते हैं। चूंकि इसकी बालियां जौ की तरह होती हैं, इससे पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए किसानों को रखवाली नहीं करनी पड़ती है। गौरतलब है कि अन्य फसलों की अपेक्षा जौ की बालियां पक्षी कम काटते हैं।

खाद का उपयोग

खेत में पहले देसी खाद फिर पूसा मंगल (एचआई 8713) गेहूं की बोवनी के समय डीएपी डाली। फसल उगने के बाद जब पहला पानी दिया तब खरपतवारनाशी वेस्टा दवा का छिड़काव किया। उसके 24 घंटे के अंदर यूरिया और सल्फर मिक्स करके छिड़काव किया। दूसरी बार यूरिया खाद का इस्तेमाल गेहूं के गलेथ अवस्था में आने पर किया। कुल दो बार यूरिया का उपयोग किया।

इल्लियों से बचाव

जैसे ही फसल तैयार होने लगी तभी इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया। इससे चिंतित किसान अनिल कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र रीवा की वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. किंजुल्क सी सिंह से सलाह ली। उन्होंने फसल को इल्लियों से बचाने के लिए किसान को दो दवाइयों प्रोपैनो फास और इनडेक्सा कार्ब का छिढ़काव का सुझाव दिया। इससे इल्लियों का पूरी तरह से खात्मा हो गया।

सिंचाई की सुविधा

किसान अनिल अपनी फसल की सिंचाई सोलर पंप से करते हैं। यह वही किसान हैं, जिनके यहां तहसील मऊगंज का पहला सोलर पंप लगा हुआ है। वो बताते हैं कि अगर मौसम साफ रहा तो सुबह छह बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सिंचाई करते हैं। इनकी फसल की सिंचाई दिन में ही होती है। खेतों को उस हिसाब से बनाया है कि सिंचाई करते समय उसमें बार-बार जाना नहीं पड़ता है।

साक्षात्कारः जागत गांव हमार से विशेष बातचीत में बोले-स्वामी अखिलेश्वरानंद

भंग गौ सदनों की बहाली से 60 फीसदी गायों को मिल जाएगा बसेरा

भोपाल। गौ संरक्षण और संवर्द्धन के संबंध में मेरा संदेश सभी के लिए यही है कि-हम सभी भारतवासी अपने पूर्वजों की गौ पालन की पारम्परिक अभिरुचि को वर्तमान में पुनः जागृत करें। गायों की उपेक्षा न करें। गायों को वध के लिए बेचना महापाप है। गौ पालन-गौ संरक्षण के लिए हमें पारंपरिक धार्मिक विधा गौ ग्रास निकालने 10 रुपया प्रतिदिन निकालकर गुल्लक में संग्रहित राशि को गौ पाष्टमी पर गौ सेवा केंद्र गौ शाला में समर्पित करना चाहिए। यह बातें मप्र गौ-पालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एवं स्वामी अखिलेश्वरानंद ने जागत गांव हमार से साक्षात्कार में कही। बातचीत के मुख्य अंश-

सवालः गौ सेवा, सनातन धर्म और संस्कृति के केन्द्र में है। इसके बावजूद गौ माता की स्थिति समाज में बेहतर नहीं है। इसका समाधान क्या है?

जवाबः सेवा शब्द भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शब्द के भावों के प्रकार बहुत बड़े हैं। गौ सेवा तो भारतीयों की मूल प्रवृत्ति, तदनुरूप गौपालन, गौसेवा, गौभक्ति सनातन धर्म की पारम्परिक अभिरुचि रही है। जहां तक सत्ता का सवाल है, सरकारें, गौपालन के लिए अपनी सुस्पष्ट नीतियों का निर्माण करें। गौवंश के लिए प्राकृतिक संसाधन, जंगल, जमीन, जल और यत्किंचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं। गाय का संबंध गावों से,जंगल से है। गौ-अभयारण्य, गौवंश वन्य बिहार, गांवों रैन बसेरा (गोठान) यह सरकार के हिस्से का काम है। वास्तव में सत्ता और समाज दोनों को ही मिलकर समस्या का समाधान खोजना होगा।

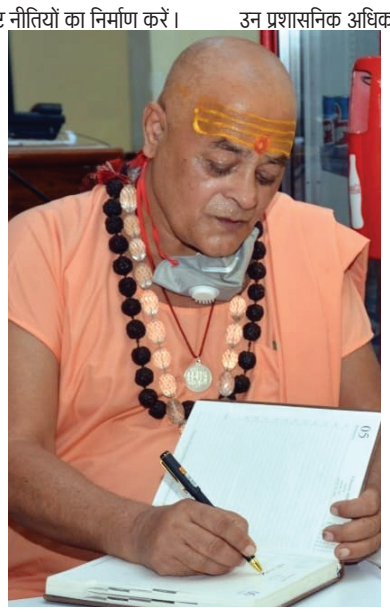

सवालः गायों के संरक्षण और संवर्धन में सत्ता और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?

जवाबः कलियुग तो अर्थ और काम का युग है। जब किसी युग में अर्थ और काम ही मूल प्रवृत्ति होकर उभर रहे होते हैं तब धर्म और मोक्ष के भाव अपना वास्तविक अर्थ खोने लगते हैं, यही कारण है कि आज गाय और सम्पूर्ण गोवंश का महत्व कम हो रहा है। गौवंश के महत्व और उसके महत्व के विविध पक्षों को युगानुकूल परिभाषित कर स्थापित करना, गौवंश की सेवा/संरक्षण/संवर्द्धन की दृष्टि से, समाधान के उपायों का यह प्रथम सोपान है, इसके लिए गाय के सभी महनीय तथ्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना युग की अनिवार्य आवश्यकता है।

सवालः मध्यप्रदेश में गौ संवर्धन के लिए कोई रूप रेखा कब तक बनेगी?

जवाबः गौमाता के संरक्षण और संवर्द्धन में सर्वप्रथम गौपालक परिवारों में गौपालन की पारम्परिक अभिरुचि को प्रोत्साहन देना और भारत के घर-घर में प्रत्येक परिवार में यह बताना जरूरी है कि गाय हमारे घर और आंगन में बने खूंटे पर ही बच पाएगी। गाय भारतीय घरों की शोभा है, वह हमारे घर की सदस्य है। भारत के किसान, गौ सेवक, गौपालक, गौ प्रेमी ही इसके जीवन की रक्षा करने में सक्षम और समर्थ हैं, यह विश्वास भरना आवश्यक है।

सवालः चरनोई भूमि को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या मिला?

जवाबः जब मैं मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्द्धन बोर्ड का दायित्व संभाल रहा था, उस समय गौवंश की समस्या के निकारण के लिए गौवंश संरक्षण और किसानों की फसल सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने एक समिति बनायी गई थी, उस समिति के सुझावों पर सरकार ने एक रोडमैप बनाया था, उसके अनुसार क्रियान्वयन की दिशा में सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं जिलों के पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए थे। गौ पालकों के लिए भी एक निर्देश जारी हुआ था। मेरा वर्तमान में यही मानना है कि-उसी रोडमैप को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। रही मेरे संघर्ष की बात तो मेरा मानना है कि-जिनको यह जिम्मेदारी दी गई है, उन प्रशासनिक अधिकारियों एवं समाज के जागरूक नागरिकों को अपनी संयुक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए।

सवालः गौ संरक्षण में मप्र अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनने की क्या संभावनाएं हैं?

जवाबः मध्यप्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां देश का सर्वाधिक गौवंश है। मप्र का 95 हजार वर्ग किमी का जंगल गायों के जीवन रक्षण एवं गोवंश के संरक्षण का आश्रय स्थल है। मप्र गौवंश के लिए बेहतर कार्य करने वाला एक माडल राज्य बनाया जा सकता है। मप्र में 1916 से 2000 तक 10 गौ सदन होते थे। अविभाजित मप्र में इन 10 गौ सदनों की भूमि लगभग 7400 एकड़ होती थी। छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हो जाने से 2 गौ सदन एवं उसकी भूमि वहां चली गई। प्रदेश में बचे आठ गौ सदनों को तत्कालीन सरकार ने भंग कर दिया। ये गौ सदन प्रायः सभी वन विभाग की भूमि पर ही बने थे। प्रदेश में भंग किए गए गौ सदनों की भूमि 6700 एकड़ के लगभग है। भंग गौ सदनों को सरकार पुनः बहाल कर दे तो प्रदेश में गौ वंश के संरक्षण की समस्या का 60 फीसदी समाधान तत्काल हो जाएगा।

सवालः गौ पालन को लेकर मानव जीवन पर प्रभाव तथा धार्मिक दृष्टि से क्या प्रभाव होगा?

जवाबः जहां तक गौ संरक्षण में सामाजिक सहभागिता का प्रश्न है तो गायों के संबंध में हमें यह धारणा बनाकर कार्य करना होगा कि गौ वंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। दूध न देने और बछड़ा-बछिया न देने पर भी तथा कृषि कार्य के अयोग्य या भार ढ़ोने की क्षमता रहित, असमर्थ होने के बाद भी गौ वंश आधारित अर्थशास्त्र समाप्त नहीं होता। गोबर-गौमूत्र पर आधारित गौवंश का अर्थशास्त्रीय महत्व सदैव बना रहता है, इस कारण सामाजिक सहभागिता भी प्रासंगिक रहती है।

फैक्ट फाइलः निराश्रित गौ वंश के व्यवस्थापन के लिए प्रदेश में लगभग 1 हजार गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। इससे एक लाख गौ वंश को आश्रय मिलेगा। मप्र में 905 गौ शालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 71 हजार गौवंश हैं। गौशालाओं के स्वावलंबन के लिए गौ-काष्ठ, पंचगव्य उत्पादन, वर्मी पिट, गमला बनाने का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है।

बेटियों की पढ़ाई के लिए दान कर दी अपनी सात एकड़ जमीन

केसली जपं के अध्यक्ष अतुल भाई बोले-राजनीति केवल माध्यम, लक्ष्य जन सेवा के साथ विकास

सागर। वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ बदली मानव समाज की जरूरतें और इसके साथ ही बदली समाज में विकास की परिभाषा। मूलभूत सुविधाओं तक सिमटे विकास का विस्तार भी जरूरतों के साथ बदलता जा रहा है। जनपद पंचायत केसली से जुड़े विकास के कुछ ऐसे सवालों के जवाब हम जानेंगे केसली जनपद पंचायत अध्यक्ष अतुल भाई डेवाड़िया से 'जागत गांव हमार' के संपादक अनिल दुबे से हुई बातचीत के मुख्य अंश-

सवालः वर्ष 2015 में आप ने जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, तब से लेकर अब तक आपने विकास को कितनी प्राथमिकता दी?

जवाबः क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए हर तरह का डेवलपमेंट जरूरी है और मैंने प्रायः सभी पहलुओं पर विकास कराने का हर संभव प्रयास किया है। हालांकि मेरी प्राथमिकता में शिक्षा, स्वास्थ्य और साई विषय हमेशा से ही शामिल रहे हैं।

सवालः क्षेत्र में शिक्षा के लिए आपने क्या प्रयास किया और कितनी सफलता मिली?

जवाबः ग्रामीण इलाकों में अक्सर हायर एजूकेशन की व्यवस्था नहीं होती और ऐसे में कई विद्यार्थी आर्थिक और सामाजिक कारणों से दूसरे शहरों में जाकर अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। अधिकतर इस समस्या से लड़कियों को रूबरू होना पड़ता है। इन समस्याओं का एक ही हल था कि केसली में कॉलेज की स्थापना हो। कॉलेज निर्माण में पहली अड़चन थी पर्याप्त सरकारी भूमि बस्ती में न होना। ऐसे में मैंने अपनी साढ़े सात एकड़ पैतृक जमीन दान कर दी और आज इसके सकारात्मक परिणाम सबके सामने हैं।

सवालः आपकी दूसरी प्राथमिकता में स्वास्थ्य शामिल है, क्या प्रयास रहे?

जवाबः उत्तम स्वास्थ्य के बगैर समृद्ध समाज की नींव नहीं रखी जा सकती और इसीलिए मैं निकट भविष्य में केसली में एक सर्वसुविधा युक्त अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रहा हूं। जो कि शीघ्र ही धरातल पर दिखाई देगी।

सवालःआज के दौर की बड़ी समस्याओं में से एक है बेरोजगार, आपने क्या कदम उठाए हैं?

जवाबः क्षेत्र में आय का मुख्य जरिया कृषि और दुग्ध उत्पादन है। मैं लगातार इन दोनों ही क्षेत्रों को उन्नत करने के लिए सब्जी और फलों के साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा हूं। यह ऐसे पारंपरिक व्यवसाय हैं जिनका शिक्षित व अशिक्षित सभी लाभ ले सकते है। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए शहर में मार्केट बिल्डिंग का निर्माण शुरू है, जिसमें करीब 134 दुकानें होंगी।

सवालः शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए क्या योजना है?

जवाबः शहर के सभी 20 वार्डों में लगातार 6 माह तक सफाई अभियान चलाया गया था। इसके साथ ही शहर में कचरा प्रबंधन के लिए भी 70 लाख रुपए की लागत से शीघ्र ही एक कार्य योजना शुरू की जाएगी। कचरा प्रबंधन के बाद शहर के बाहर कचरा निष्पादन के लिए भी पांच करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा। शहर के सौंदर्यकरण की बात करें तो मंदिरों का निर्माण कराए जाने के साथ ही दो पार्क भी तैयार करवाए जा रहे हैं।

सवालःशहरवासियों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कदम उठाए गए?

जवाबः शहर के करीब 95 फीसदी हिस्से में पाईप लाइन बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम पंचायत टड़ा में भी नल जल योजना का कार्य आरंभ है। आदिवासी बाहुल्य ग्राम खटोला में तालाब बनवाया गया है। इसके साथ ही शहर सहित ग्राम पंचायतों के जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू है। वहीं हैंडपंपों के आसपास रिचार्ज बनवाने का काम भी जारी है।

सवालःराजनीतिक भविष्य को लेकर आपकी क्या रणनीति है?

जवाबः मेरा उद्देश्य जन सेवा करना है और इसके लिए मैने राजनीति को अपना माध्यम चुना है। जनपद अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र की जनता का स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी प्रेरणा हैं और यही मुझे सेवा और विकास कार्य करने लिए प्रेरित करते हैं। भविष्य में भी सेवा कार्य ही जारी रखने हैं और इसके लिए पार्टी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करूंगा।

आदर्श बनी महूना गूजर पंचायत, जज्बे ने बदली तस्वीर

» विकास कार्यों ने बदला पंचायत का नजारा, लॉकडाउन में श्रमिकों को मिला काम

भगवान, सिंह प्रजापति, राहतगढ़

कोरोनाकाल में मजदूरों के लिए वरदान बनी मनरेगा ने पंचायतों की तस्वीर बदल दी है। केंद्र और राज्य सरकारों की मदद से गांव में न सिर्फ विकास की कार्य शुरू हुए हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को गांव में ही रोजगार भी मिला है। वहीं भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। कुछ ऐसा ही स्थिति सागर जिले की राहतगढ़ जनपद पंचायत के महूना गूजर पंचायत की है। यहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की सक्रियता से पंचायत में विकास कार्यों ने गांव की तस्वीर बदल दी है। यह संभव हो सका है, गांव के लिए कुछ करने के जज्बे के कारण। यहां सरपंच, सचिव एवं रोजगार के इसी जज्बे ने पंचायत की तस्वीर बदल दी है। अब महूना गूजर पंचायत भी आदर्श पंचायत का रूप ले चुकी है।

कभी होता था कीचढ़, आज फर्राटे भर रहे वाहनः पंचायत के गांव में बारिश के दिनों में सड़क पर निकलना संभव नहीं हो पाता था। यहां तक की लोग कीचढ़ के चलते घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन सरपंच तारा सिंह गूजर, सचिव रामस्वरूप अहिरवार एवं रोजगार सहायक भूपेंद्र दुबे ने ग्रामीणों की मंशा को आकार देते हुए पंचायत की तस्वीर ही बदल दी। अब गांव में कीचढ़ की जगह आरसीसी सड़क है। साथ ही गांव में अन्य मार्ग पर भी सड़क प्रस्तावित है, जिसकी तस्वीर भी जल्द ही बदल जाएगी। बताया जाता है कि पंचायत में 20 के करीब ऐसी सड़कें बनी हैं, जिससे गांव में विकास की तस्वीर दिख रही है।

पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का बदला नजाराः गांव में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार है। इनकी तस्वीर किसी आदर्श कार्यालय जैसी है। खासकर आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लुभा रहा है। यहां बच्चे न सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पोषण आहार भी मिल रहा है। यही नहीं पंचायत भवन में आगतुकों के लिए बेहरत माहौल तैयार किया गया है, ताकि यहां कार्य से आने वाले लोगों को सहूलियत हो सके। आंगनबाड़ी में बच्चों को घर जैसा माहोल उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां बच्चे पढ़ाई के बाद खुशी-खुशी घर लौटते हैं। बच्चों को प्रेरित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर फूलों का बगीचा भी लगाया गया है, जहां खिले रंग-बिरंगे फूल नौनिहालों को रोजाना आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए प्रेरित करते हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
रायसेन, बृजेश ठाकुर-9926777555
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
गंजबासौदा, प्रदीप श्रीवास्तव- 7987780456
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति -9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)